भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-432
बुधवार, 20 नवम्बर, 2019/29 कार्तिक, 1941 (शक)

देश में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

432. श्रीमती विप्लव ठाकुरः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य सहित देश में पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या वर्ष 2018-19 से देश में रोजगार के अवसरों में कमी आई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास देश में रोजगार सृजन करने के लिए कोई ठोस योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में हिमाचल प्रदेश सहित रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वाले, जिनमें यह आवश्यक नहीं है कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या उपलब्ध सीमा तक नीचे अनुबंध-। में दी गई है।

(ख से घ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) नीचे दिया गया है।

कामगार जनसंख्या अनुपात (%)	
सर्वेक्षण*	**अखिल भारत**
2017-18 (पीएलएफएस)	46.8%
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	50.5%
2013-14 (श्रम ब्यूरो)	53.7%

(टिप्पणीः *पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में विशेषकर आरक्षित श्रेणियों हेतु रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्टार्ट-अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है, जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 20.11.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 432 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जनवरी-अगस्त 2017 (अनंतिम) के दौरान देश में उपलब्ध सीमा तक रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रोजगार चाहने वाले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	रोजगार चाहने वाले (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	9.18
2	अरुणाचल प्रदेश	1.02
3	असम	19.47
4	बिहार	7.89
5	छत्तीसगढ़	22.51
6	दिल्ली	12.63
7	गोवा	1.19
8	गुजरात	5.85
9	हरियाणा	7.77
10	**हिमाचल प्रदेश**	**8.35**
11	जम्मू और कश्मीर	2.33
12	झारखंड	4.66
13	कर्नाटक	3.38
14	केरल	34.99
15	मध्य प्रदेश	19.36
16	महाराष्ट्र	34.29
17	मणिपुर	6.08
18	मेघालय	0.41
19	मिजोरम	0.36
20	नागालैंड	0.68
21	ओडिशा	9.80
22	पंजाब	3.45
23	राजस्थान	5.30
24	सिक्किम #	-
25	तमिलनाडु	76.88
26	तेलंगाना	2.88
27	त्रिपुरा	9.00
28	उत्तराखंड	28.43
29	उत्तर प्रदेश	77.61
30	पश्चिम बंगाल	0.43
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.19
32	चंडीगढ़	0.09
33	दादर और नगर हवेली	0.10
34	दमन और दीव	0.19
35	लक्षद्वीप	2.25
36	पुडुचेरी	9.60
	योग@	**428.60**

स्रोत: रोजगार कार्यालय सांख्यिकी, रोजगार महानिदेशालय

टिप्पणी: # इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है;

@ हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।